भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.-2429

उत्तर देने की तारीख-04.08.2025

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क

†2429. **श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल**:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) को अपनाए जाने की क्या स्थिति है;
(ख) क्या गुजरात में कौशल आधारित अथवा व्यावसायिक क्रेडिट को डिग्री कार्यक्रमों में समेकित किया जा रहा है; और
(ग) वर्ष 2024-2025 में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) के साथ संरेखण की सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में शिक्षा को अपेक्षाकृत अधिक समग्र, व्यवहार्य बनाने के साथ-साथ इसे शैक्षणिक, कौशल और व्यावसायिक शिक्षा में एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है। इस संकल्पना के अनुरूप, प्रारंभिक, स्कूल, उच्चतर तथा व्यवसायपरक शिक्षा और प्रशिक्षण को शामिल करते हुए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) को एक व्यापक क्रेडिट फ्रेमवर्क के रूप में शुरू किया गया है। यह विभिन्न प्रकार के शिक्षा आयामों जैसे अकादमिक शिक्षा, व्यावसायिक कौशल, और अनुभवात्मक अधिगम, जिसमें प्रासंगिक अनुभव और दक्षता/पेशेवर स्तर प्राप्ति शामिल है, के क्रेडिटीकरण को एकीकृत करता है।

एनसीआरएफ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) सहित अन्य संगठनों के सहयोग से संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। यह मूल्यांकन के अध्यधीन सभी प्रकार के अधिगम व असाइनमेंट के क्रेडिटीकरण तथा क्रेडिट्स के संचयन, भंडारण, अंतरण और पुनः उपयोग की सुविधा प्रदान करता है, यह व्यवसायपरक और सामान्य शिक्षा के बीच भेद को समाप्त करता है तथा उनके बीच अकादमिक समतुल्यता स्थापित करते हुए शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के बीच गतिशीलता को संभव बनाता है।

गुजरात सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, गुजरात राज्य ने अपने उच्चतर शिक्षा संबंधी सुधारों को राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) के साथ सक्रिय रूप से अनुकूलित किया है। गुजरात सरकार ने यूजीसी के एनसीआरएफ दिशानिर्देशों के आधार पर अवर स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन हेतु जुलाई 2023 में निदेश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके अतिरिक्त, गुजरात में 12 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से नई क्रेडिट संरचना कार्यान्वित की है और गुजरात के सभी 66 निजी विश्वविद्यालयों ने इस फ्रेमवर्क को अपना लिया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मई, 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) हेतु दिशानिर्देश जारी किए। तदनुसार, गुजरात सरकार ने एनएचईक्यूएफ को अपनाने और इसके कार्यान्वयन हेतु राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को निदेश जारी किए हैं।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने आईआईटी मद्रास और प्रतिष्ठित उद्योग भागीदारों की सहकार्यता से दिनांक 27 फरवरी 2024 को स्वयम प्लस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। यह प्लेटफॉर्म अग्रणी उद्योग और शैक्षणिक विशेषज्ञों के साथ साझेदारी में विद्यार्थियों/शिक्षार्थियों को उच्च गुणवत्ता पूर्ण अधिगम और प्रमाणन कार्यक्रम प्रदान करता है, जिससे उन्हें कौशल को पुनः प्राप्त करने, कौशलोन्नयन करने और रोजगार के लिए तैयार होने में मदद मिलती है। शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी मद्रास ने अग्रणी उद्योग भागीदारों के साथ 65 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। दिनांक 25 जुलाई, 2025 तक, 16 विभिन्न क्षेत्रों में 400 से अधिक पाठ्यक्रम इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, और 3 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने अपने कौशल संवर्धन के लिए नामांकन कराया है।

शिक्षा मंत्रालय ने युवाओं को कार्यस्थल पर प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनकी नियोजनीयता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) कार्यान्वित की है। विगत 5 वित्तीय वर्षों में, अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक, एनएटीएस योजना ने 12.94 लाख प्रशिक्षुओं को नियोजित किया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 5.23 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को नियोजित किया गया है।

***